

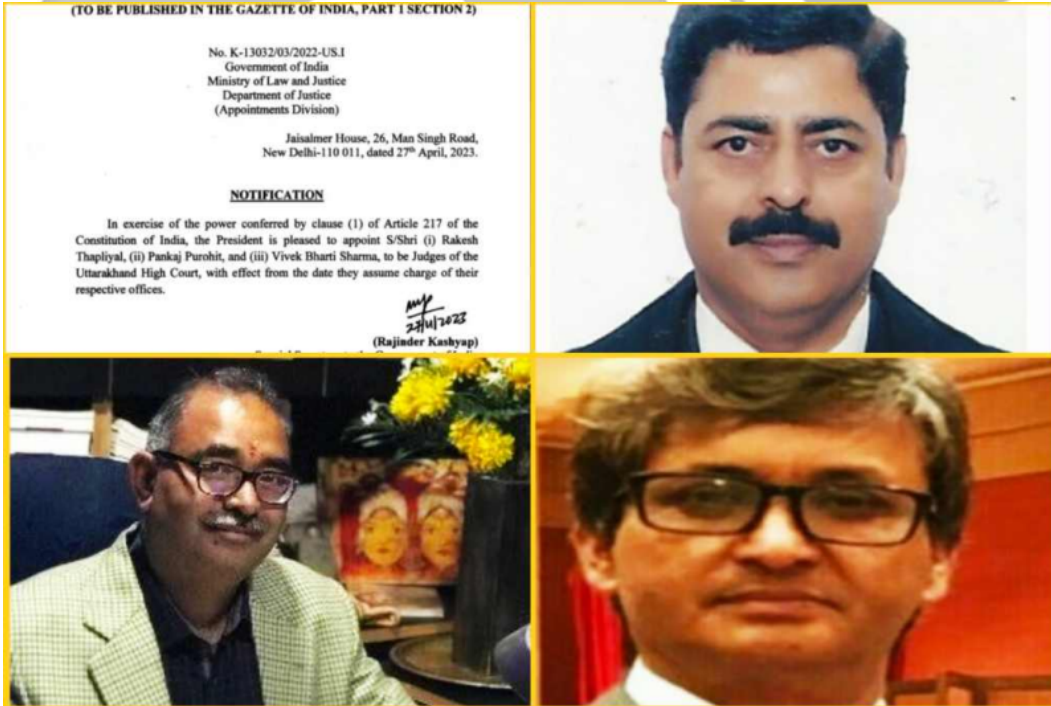
उत्तराखण्ड हाईकोर्ट में तीन नए जजों की नयुक्तिको राष्ट्रपतकी मंजूरी

चर्चा में क्यों?

27 अप्रैल, 2023 को उत्तराखण्ड हाईकोर्ट में तीन नए जजों की नयुक्तिको राष्ट्रपतकी मंजूरी मलि गई है। इनमें वरषिठ अधविकता राकेश थपलथिल, अधविकता पंकज पुरोहति और हाईकोर्ट के रजसिटरार जनरल वविक भारती शरमा शामिल हैं। इन्हें मुख्य न्यायाधीश वपिनि सांघी शपथ दलिरंगे।

प्रमुख बदि

- वदिति है कित्तराखण्ड हाईकोर्ट में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहति पाँच जज कारररत थे। अब न्यायाधीशों की संख्या आठ हो जाएगी।
- मूलतः पौड़ी गढवाल के खतसयूं शरीकोट नविसी वरषिठ अधविकता राकेश थपलथिल उत्तराखण्ड हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के अससिटेड सॉलसिटर जनरल रहे। उन्हें 2014 से तीन बार यह ज़मिमेदारी मलि चुकी है। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट बनने के बाद वे 2000 में नैनीताल हाईकोर्ट आ गए। 2002 में केंद्र सरकार के स्टेंडिंग काउंसलि बने और 11 महीने बाद इस पद से इस्तीफा दे दिया।
- रजसिटरार जनरल वविक भारती शरमा उत्तराखण्ड बैच के 2005 के हायर ज्यूडिशियरी सर्वसि के न्यायकि अधकिारी हैं। उन्होंने दलिली हाईकोर्ट में 1990 में वकालत प्रारंभ की और दलिली सरकार की ओर से दलिली हाईकोर्ट में स्टेंडिंग काउंसलि नयुक्त हुए। बाद में वह भारत सरकार के स्टेंडिंग काउंसलि बने। हायर ज्यूडिशियल सर्वसि में चयनति होने के बाद वह अपर ज़िला जज हरदिवार, हल्दवानी, नैनीताल रहे।
- वविक भारती शरमा प्रसिपिल ज़िला जज पथोरगढ़ और पौड़ी भी बने। उन्होंने राज्यपाल के वधि सलाहकार के रूप में भी कार्य कथिा है। वह वाणजियकि कर ट्रबियूनल के चेयरमैन, उजाला भवली के नदिशक और ज़िला जज हरदिवार भी रहे हैं। अप्रैल 2022 में उन्हें हाईकोर्ट का रजसिटरार जनरल बनाया गया।
- देवल गवाड़ चमोली नविसी अधविकता पंकज पुरोहति का 1992 में इलाहाबाद बार काउंसलि में पंजीयन हुआ। 1997 से वह इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत करने लगे। उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद उत्तराखण्ड हाईकोर्ट में वकालत करने लगे। वह बीमा कंपनयिों, ज़िला पंचायतों, नगरपालकिाओं, राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, सीतापुर नेत्र चकित्सालय आदि के अधविकता रहे हैं।
- मई 2017 में वह उत्तराखण्ड हाईकोर्ट में उप महाधविकता बने, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने यह पद छोड़ दिया।



PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/president-approves-appointment-of-three-new-judges-in-uttarakhand-high-court>

